

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2614**

जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026
18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए विनिवेश योजना

**2614. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री अनिल यशवंत देसाई:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की विनिवेश योजना का ब्यौरा क्या है,
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी बेचने और उक्त व्यावसायिक कार्यों में भाग लेने के लिए निजी संस्थाओं को आमंत्रित करने के क्या कारण हैं,
(ग) गत दस वर्षों के दौरान निजी पक्षों को सौंपे गए उपक्रमों की सफलता के संबंध में सरकार का क्या आकलन है:
(घ) क्या उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय
(श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (ख): सरकार (i) विभिन्न सेबी-अनुमोदित विधियों जैसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापस-खरीद आदि के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से और (ii) रणनीतिक विनिवेश अर्थात् प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ-साथ एक रणनीतिक खरीदार को सरकारी शेयरधारिता की पूरी अथवा वस्तुगत बिक्री करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में विनिवेश करती है।

जहां अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से सीपीएसई के सार्वजनिक प्रवाह में वृद्धि होती है और नागरिकों/निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से इन कंपनियों द्वारा सृजित मूल्य से लाभ उठाने में सक्षम बनाया जाता है, वहां रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण इस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में स्वयं को रोक लेना चाहिए, जहां प्रतिस्पर्धी बाजार परिपक्व हो गए हैं और पूंजी निवेश, तकनीकी उन्नयन और कुशल प्रबंधन व्यवहारों जैसे विभिन्न कारकों के कारण ऐसी इकाइयों की आर्थिक क्षमता को रणनीतिक निवेशक के हाथों में बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है।

विनिवेश एक सतत् प्रक्रिया है और विशिष्ट लेन-देन का निष्पादन/संपूर्णता बाजार की स्थितियों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, भू-राजनीतिक कारकों, निवेशकों के हित और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। विनिवेश लेन-देन की बाजार के प्रति संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, विनिवेश के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ग) से (ड): पिछले दस वर्षों में पारदर्शी, खुली और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित सीपीएसई का निजीकरण किया गया है:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	सीपीएसई/इकाई का नाम	अधिग्रहणकर्ता का नाम
1	2021-22	एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एआइएक्सएल और एआइएसएटीएस (संयुक्त उद्यम)	मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड
2	2022-23	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआइएनएल)	टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
3	2024-25	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), एमएसटीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी	मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड

विभाग ने इन निजीकृत सीपीएसई की परिचालनात्मक, तकनीकी और प्रबंधन क्षमता का कोई औपचारिक आकलन नहीं किया है। तथापि, आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2019-20 ने 11 सीपीएसई, जिनमें वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक रणनीतिक विनिवेश किया गया था, के मामले में निजीकरण के लाभ का विश्लेषण किया है। विश्लेषण से पता चलता है कि इन निजीकृत सीपीएसई ने, औसतन, अपने निवल मूल्य, निवल लाभ, परिसंपत्तियों पर प्राप्ति, इक्विटी पर प्राप्ति, सकल राजस्व, निवल लाभ मार्जिन, बिक्री में वृद्धि और प्रति कर्मचारी सकल लाभ के संदर्भ में अपने समकक्षों की तुलना में निजीकरण के बाद बेहतर कार्य-निष्पादन किया है।
